P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-3* June - 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

श्रमिकों का रिवर्स पलायनः– बिहार की अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ

Reverse Migration of Workers: Challenges and Prospects Facing Bihar's Economy

Paper Submission: 20/06/2020, Date of Acceptance: 29/06/2020, Date of Publication: 30/06/2020

नीलू कुमारी
एसोसिएट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोईवाला, देहरादून,
उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

विश्वभर में कोरोना महामारी के फैलाव के साथ ही भारत में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण जहाँ लाखों लोगों की जानें गयी है वहीं अर्थव्यवस्था के सामने कई संकट एव चुनौतियाँ भी खड़ी हुई हैं। उन्ही चुनौतियों में से एक बहुत ही गम्भीर चुनौती है श्रमिकों का बड़े शहरों से अपने मूल राज्य की ओर रिवर्स पलायन। कोरोना संकट की शुरूआत चीन के वुहान शहर से हुई और भारत में 30 जनवरी 2020 को इसका पहला मामला सामने आया, लेकिन धीरे–धीरे इसने महामारी का रूप धारण कर लिया। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये भारत में 25 मार्च 2020 से एक के बाद एक लॉकडाउन शुरू हो गये जो 31 मई 2020 तक मुख्य रूप से चला है। इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारे उद्योग–धन्धे, व्यापार, परिवहन इत्यादि लगभग बन्दप्राय हो गये। इस बन्दी से रोजगार एवं आय के साधन समाप्त होते देख भारत के विभिन्न शहरों में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने अपने घर की ओर पलायन करना प्रारंभ कर दिया जो अभी तक जारी है। लॉकडाउन के कारण बिहार में भी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रामिकों की वापसी शुरू हो गयी है, जहाँ से उत्तर–प्रदेश के बाद दूसरे नम्बर पर सबसे ज्यादा श्रमिक दूसरे प्रदेश में जाकर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। हालाँकि कितने श्रमिकों की वापसी होगी इस संबन्ध में कोई निश्चित आँकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जो आँकड़े उपलब्ध हैं उससे बिहार में सबसे ज्यादा 23.6 लाख श्रमिकों की वापसी हो चुकी है। इन श्रमिकों के रिवर्स पलायन से बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं क्या चुनौतियाँ होंगी बिहार राज्य के सामने यह जानने की कोशिश की गई है। अध्ययन में यह पाया गया है कि बिहार में श्रमिकों के रिवर्स पलायन से गरीबी, बेरोजगारी एवं भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा। लेकिन यदि इन श्रमिकों के लिए सही नीति अपनाकर इन्हें राज्य के विकास कार्यों में लगाया जाए तो यह रिवर्स पलायन बिहार में नई विकास सम्भावनाओं का उदय भी कर सकता है।

With the spread of the corona epidemic worldwide, corona infection is also increasing rapidly in India. While millions of people have lost their lives due to Corona infection, many crises and challenges have also arisen in front of the economy. One of the most serious challenges is the reverse migration of workers from big cities to their original state. The Corona crisis began in the Wuhan city of China and its first case came to light in India on 30 January 2020, but it gradually took the form of an epidemic. In order to prevent the corona epidemic, one-on-one lockdown started in India from 25 March 2020, which has continued till 31 May 2020. During this lockdown, all industries-businesses, trade, transportation, etc., except essential services, have almost come to a standstill. Seeing the loss of employment and income from this prison, the workers of unorganized sector working in different cities of India started migrating to their home which is still going on. Due to the lockdown, a large number of migrant laborers have also started returning in Bihar, from where the maximum number of laborers go to another state to earn their livelihood after the upliftment. Although no definite statistics are available at this time regarding how many workers will be returned, but the figures which are available have led to the maximum return of 23.6 lakh workers in Bihar. The reverse migration of these workers will have an impact on the economy of Bihar state and what challenges will be faced by the state of Bihar. It has been found in the study that reverse migration of workers in Bihar will increase poverty, unemployment and population pressure on land. But if these workers are adopted in the development works of the state by adopting the right policy for these workers, then this reverse migration can also lead to the rise of new development possibilities in Bihar.

मुख्य शब्द : रिवर्स पलायन, कोरोना, लॉकडाउन, बेरोजगारी, असंगठित क्षेत्र, जीविकोपार्जन
Reverse Migration, Corona, Lockdown, Unemployment, Unorganized Sector, Livelihood

प्रस्तावना

मानवीय श्रम उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। किसी देश की श्रम शक्ति पर ही उस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। उत्पादन के अन्य साधन भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं परन्तु इनका प्रयोग भी मनुष्य (श्रम) के द्वारा ही किया जाता है। गगनचुम्बी भवनों का निर्माण, विशालकाय कारखानों की स्थापना और पहाड़ों को छेदकर सुराख करने से लेकर नदियों की तूफानी धारा का रूख मोड़ने का श्रेय श्रम को ही प्राप्त है। एडम स्मिथ (1776) ने श्रम के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि समस्त सम्पत्ति का श्रोत 'श्रम' ही है। श्रम के अन्तर्गत मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक दोनो प्रकार के श्रम को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ हम जिस श्रम का जिक्र कर रहे हैं उसका सम्बन्ध प्रवासी श्रमिक से है जो असंगठित क्षेत्र में अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से विकसित हुआ है और इसमें अधिकांशतः वे लोग शामिल हैं जो गाँव में परम्परागत कार्य करते हैं और शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण, उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग इत्यादि में कार्य करते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार भारत के कुल कार्यबल का लगभग 93 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है।

असंगठित क्षेत्र के इन श्रमिकों का उत्पादन में इतना अधिक योगदान होते हुए भी कोविड–19 की संक्रामकता एवं अनिश्चितता की रोकथाम के लिए बार–बार लागू लॉकडाउन एवं बन्दप्रायः उद्योग धंधे एवं उत्पादन के कारण उन्हें बेरोजगार एवं आयविहीन होना पड़ा। क्योंकि संबन्धित राज्यों द्वारा, जहाँ ये कार्य करते थे, कोई खास जिम्मेदारी नही उठाई गई। ऐसी स्थिति में प्रवासी श्रामिक भूखे–प्यासे, पैदल साइकिल सवार होकर या बाद में सरकार द्वारा चलाये गये श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपनी मातृभूमि की ओर रिवर्स पलायन करने लगे। लॉकडाउन के दौरान होने वाला यह पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से अलग है।

सी0पी0 त्रिपाठी (2017) ने कहा है कि आमतौर पर एक राज्य या देश से दूसरे राज्य या देश में होने वाला पलायन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो लोग रोजगार एवं व्यवसाय के श्रेष्ठ अवसर, अधिक आय अर्जित करने के अवसर, शिक्षा, प्रशिक्षण, मनोरंजन आदि से प्रभावित होकर, आकर्षक कारक (Pull Factors) के कारण गाँव से शहर की ओर जाते हैं, दूसरी ओर प्रत्याकर्षक कारकों (Push Factors) से बाध्य होकर जिनमें रोजगार अवसरों का अभाव, शिक्षा, सामाजिक तिरस्कार, राजनीतिक, जातीय या धार्मिक, प्राकृतिक आधार आदि हैं।

C. Annie Jane (2016) के अनुसार रोजगार की तलाश में होने वाले आन्तरिक पलायन का उन दोनो क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ से ये आते हैं और जहाँ ये पलायन कर पहुँचते है। ये पलायन स्थायी एवं अस्थायी दोनो हो सकते हैं।

लेकिन इस समय महानगरों एवं दूसरे राज्यों से श्रमिकों का अपने राज्य एवं गाँव की ओर रिवर्स पलायन हो रहा है जो निःसंदेह संबन्धित राज्यों के लिए चिन्ता का विषय है। विश्व बैंक अप्रैल, 2020 के अनुसार भारत में लॉकडाउन से लगभग 4 करोड़ प्रवासी प्रभावित हुए है। Bernard D' Sami के एक लेख मई, 2020 के अनुसार कुछ प्रमुख राज्य जहाँ से सबसे ज्यादा श्रमिक प्रवासित होते हैं उनमें उत्तर–प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा एवं उत्तराखण्ड मुख्य हैं तथा जहाँ ये प्रवासित होते हैं उसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल हैं। इन प्रवासियों की संख्या 1991 से 2011 में 220 मिलियन से 454 मिलियन हो गई है (जनगणना 1991,2001,2011)। इसमें बिहार दूसरे नम्बर पर आता है जहाँ से सबसे ज्यादा श्रमिक दूसरे राज्य में पलायन करते हैं।

इस समय लॉकडाउन के दौरान एवं उसके बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा 23.6 लाख श्रमिकों की वापसी हो चुकी है जैसा कि सरकारी आँकड़े बता रहे हैं और आगे भी और अधिक वापसी हो सकती है। लेकिन अचानक आई हुई इस आपदा को झेलने एवं बेराजगार होकर खाली हाथ लौटते हुए लाखों श्रमिकों के सैलाब को झेलने एवं रोजगार प्रदान कर आर्थिक रूप से शसक्त करने के लिए शायद ही कोई राज्य पहले से ही तैयार हो। यह किसी भी राज्य के साथ बिहार राज्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। Belgion-born (01अप्रैल, 2020) ने तो कहा है कि रिवर्स पलायन से बिहार की स्थिति सबसे खराब होगी। इस पेपर में यही जानने का प्रयास किया गया है कि आखिर बिहार के सामने इस रिवर्स पलायन से क्या–क्या चुनौतियाँ खड़ी होंगी और क्या सम्भावनाएँ भी हैं?

अध्ययन का उद्देश्य

1. इस पेपर का मुख्य उद्देश्य रिवर्स पलायन का बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों एवं चुनौतियों का अध्ययन करना है।
2. साथ ही इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने सुझाव भी देना है।

शोध प्रविधि

यह शोध द्वितीयक समंक पर आधारित है। द्वितीय समंक का संकलन मुख्य रूप से विभिन्न शोध पत्रों, सामयिक लेखों, इन्टरनेट, भारत की जनगणना 1991, 2001, 2011, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20, एवं NSSO रिपोर्ट है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों एवं किताबों का उपयोग भी किया गया है। समंकों के विश्लेषण के लिए अनुपात एवं प्रतिशत विधि का उपयोग किया गया है। चूँकि कोरोना संकट एक तत्कालिक समस्या है इसलिए इस शोध पत्र में तात्कालिक चुनौतियों एवं प्रभाव पर फोकस किया गया है।

बिहार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति

बिहार एक सघन आबादी वाला राज्य है जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। जनसंख्या का यह घनत्व पूरे भारतवर्ष के प्रति किलोमीटर निवास करने वाली जनसंख्या (382 प्रति किलोमीटर) की लगभग तीन गुणी है जिसे इस तालिका (1) में देख सकते हैं। गरीबी के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे 33.74 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यह प्रतिशत भी भारत के सभी राज्यों से ज्यादा है। भारत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 21.9 है। हालाँकि बिहार में 2004–05 के 54.4 प्रतिशत के मुकाबले इसमें 2011 में 20.7 प्रतिशत की कमी आई है (तालिका 2) बिहार की प्रतिव्यक्ति व्यय 2011–12 में 778 रूपये ग्रामीण एवं 923 रूपये शहरी क्षेत्र में है जो पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण एवं शहरी प्रतिव्यक्ति व्यय क्रमशः 816 रूपये एवं 1000 रूपये से कम है।

तालिकाः 1
जनसंख्या (मिलियन)

		कुल	ग्रामीण	शहरी
बिहार	2001	82.9	74.3	8.7
	2011	104.1	92.3	11.8
भारत	2001	1028.7	742.5	286.1
	2011	1210.6	833.7	377.1
		प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व	शहरीकरण (%)	दशकीय वृद्धि दर(%)
बिहार	2001	880	10.5	28.6
	2011	1106	11.3	25.1
भारत	2001	325	27.8	21.5
	2011	382	31.2	17.6

स्रोत : जनगणना 2001, 2011

तालिकाः 2
बिहार और भारत का गरीबी अनुपात

क्षेत्र		1993–94	1999–2000	2004–05	2011–12	2004–05 एवं 2011–12 के बीच गरीबी अनुपात की कमी
बिहार	ग्रामीण	58.2	44.3	55.7	34.1	21.6
	शहरी	34.5	32.9	43.7	31.2	12.5
	कुल	55.0	42.6	54.5	33.7	20.7
भारत	ग्रामीण	37.3	27.1	41.8	25.7	16.1
	शहरी	32.1	23.6	25.7	13.7	12.0
	कुल	36.0	26.1	37.2	21.9	15.3

प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (रूपये में)

बिहार	ग्रामीण	–	–	433	778	–
	शहरी	–	–	526	923	–
भारत	ग्रामीण	–	–	4217	816	–
	शहरी	–	–	579	1000	–

स्रोतः योजना आयोग, भारत सरकार

बेरोजगारी एवं श्रम जनसंख्या अनुपात

बिहार में बेरोजगारी की दर 2018 में ग्रामीण क्षेत्रों में 6.8 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 9.0 प्रतिशत है जबकि भारतवर्ष में ग्रामीण प्रतिशत 5.3 एवं शहरी बेरोजगारी 7.7 प्रतिशत है। यानि बिहार में बेरोजगारी के मामले भारत के औसत से ज्यादा हैं। हालाँकि केरल, झारखण्ड जैसे कुछ राज्य इस मामले में बिहार से भी खराब स्थिति में हैं जैसा कि तालिका (3) से स्पष्ट है। यदि हम बिहार की बेरोजगारी दर में वृद्धि पर गौर करें तो 2004–05 से 2017–18 के बीच ग्रामीण बेरोजगारी दर में वृद्धि शहरी बेरोजगारी की वृद्धि की तुलना में कहीं ज्यादा है। इस दौरान शहरी बेरोजगारी 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत हो गई जबकि ग्रामीण बेरोजगारी लगभग 3 गुणी वृद्धि के साथ 1 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गई है। इसे हम तालिका (4) में देख सकते है।

तालिकाः 3
भारत के विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी दर

राज्य	ग्रामीण	शहरी	राज्य	ग्रामीण	शहरी
आंध्र प्रदेश	3.6	6.6	महाराष्ट्र	3.2	7.4
आसाम	8.1	6.3	उड़ीसा	6.9	8.4
बिहार	6.8	9.0	पंजाब	7.6	7.7
छत्तीसगढ़	2.5	7.5	राजस्थान	4.4	7.2
गुजरात	5.2	4.2	तमिलनाडु	7.9	6.9
हरियाणा	9.2	6..9	तेलांगना	6.5	9.4
झारखंड	6.8	10.4	उत्तर प्रदेश	5.4	9.5
कर्नाटक	3.9	6.5	प0 बंगाल	3.8	6.4
केरल	10.0	13.2	भारतवर्ष	5.3	7.7
मध्य प्रदेश	3.4	7.6			

Source: Periodic Labour Force Survey, NSSO, 2018

तालिकाः 4

बिहार में बेरोजगारी दर (%)

	2004–05	2009–10	2011–12	20017–18
ग्रामीण				
पुरूष	1.8	2.1	2.7	7.2
महिला	0.2	1.3	8.2	2.3
कुल	1.5	2.0	3.2	7.0
शहरी				
पुरूष	6.7	6.3	4.5	9.2
महिला	4.1	1.6	16.5	6.2
कुल	6.4	7.3	5.6	9.0

Source: Handbook of Statistics on Indian States, Reserve Bank of India and Periodic Labour Force Survey, 2019

बेरोजगारी के साथ ही बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो कुल कार्य के लिए तैयार श्रमिकों में से वैसे श्रमिकों की संख्या को बताता है जो वास्तव में कार्य में लगे हुए हैं, काफी कम हैं। 2017–18 में श्रम जनसंख्या अनुपात (WPR) ग्रामीण क्षेत्र में 35.6 एवं शहरी क्षेत्र में 34.7 है। जबकि भारत में यह अनुपात ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए क्रमशः 48.1 एवं 43.9 है। तालिका (5) के अनुसार, बिहार इस मामले में सभी राज्यों में सबसे पीछे है। इससे हमें बिहार में श्रमिकों के लिए कार्य उपलब्धता की स्थिति का पता चलता है।

तालिकाः 5

भारत के विभिन्न राज्यों में कार्य जनसंख्या अनुपात, 2017–18

राज्य	ग्रामीण	शहरी	राज्य	ग्रामीण	शहरी
आंध्र प्रदेश	61	49.3	महाराष्ट्र	55	44.7
टासाम	43.8	42.8	उड़ीसा	45.6	41.1
बिहार	35.6	34.7	पंजाब	41.1	45.8
छत्तीसगढ़	65.5	50	राजस्थान	50.3	41.5
गुजरात	49.1	45.1	तमिलनाडु	53.7	47.9
हरियाणा	41.3	42.4	तेलांगना	52.9	45.2
झारखंड	43.2	36	उत्तर प्रदेश	42.5	39.3
कर्नाटक	51.9	44.9	प0 बंगाल	48.5	46.1
केरल	41.9	40.2	भारतवर्ष	48.1	43.9
मध्य प्रदेश	57.3	45.3			

Source: Periodic Labour Force Survey, (MOSII) NSSO, 2018

कृषि क्षेत्र पर गौर करें तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है लेकिन फिर भी किसानों की आय देश में सबसे कम सिर्फ 3,568 रूपये प्रतिमाह है। जबकि कुछ प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में, पंजाब में 18,059 रूपये, हरियाणा में 14,414 रूपये, जम्मू कश्मीर में 12,583 रूपये, केरल 11,888 रूपये, असम 11,752 रूपये, उत्तर प्रदेश 4,923 रूपये, झारखण्ड 4,721 रूपये, उड़ीसा 3,980 रूपये और हिमाचल प्रदेश 3,980 रूपये प्रतिमाह है (तालिका 6)। किसानों की आय कम होने का कारण कृषि की निम्न उत्पादकता, बढ़ती उत्पादन लागत, फसलों का उचित मूल्य न मिलना, कृषि रोड़मैप की विफलता, पूँजी का अभाव एवं श्रमिकों का पलायन इत्यादि है।

तालिकाः 6

कृषि कों की प्रतिमाह आय (2018–19)

राज्य	प्रतिमाह आय (रूपये में)
बिहार	3,558
पंजाब	18,059
हरियाणा	14,414
जम्मू कश्मीर	12,583
केरल	11,888
असम	11,752
उत्तर प्रदेश	4,923
झारखंड	4,721
उड़ीसा	3,980
हिमाचल प्रदेश	3,980

Source: Directorate of Economics and Statistics

इसके अतिरिक्त बिहार में औद्योगिक इकाइयाँ भी भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम हैं। साथ ही इन औद्योगिक इकाइयों/कारखानों में प्रति फैक्टरी रोजगार की क्षमता भी काफी कम है। जैसा कि तालिका 7 से स्पष्ट होता है कि बिहार में भारत के कुल कारखानों का केवल 0.8 प्रतिशत कारखाना है और प्रति कारखाना औसत केवल 40 व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता है।

तालिकाः 7

State-wise Persons Engaged in Industrial Sector (2016-17)

State	No. of Factories in Operation	Present Share in Total	Employment Per Factory
आंध्र प्रदेश	13,084	3.8	43.1
बिहार	2,908	0.8	40.0
छत्तीसगढ़	2,,874	1.3	65.2
गुजरात	18,980	11.0	86.1
हरियाणा	6,854	5.5	1207
झारख्ंड	2,449	1.3	77.2
कर्नाटक	10,748	7.1	99.1
केरल	6,748	2.1	47.4
मध्य प्रदेश	3,974	2.5	93.7
महाराष्ट्र	21,095	12.9	91.3
उड़ीसा	2,694	1.8	101.2
पंजाब	10,705	4.4	61.3
राजस्थान	8,263	3.6	64.5
तमिलनाडु	31,614	16.2	76.2
तेलांगना	12,725	4.9	56.9
उत्तर प्रदेश	12,894	6.8	78.6
प0 बंगाल	8,604	4.3	74.5
भारतवर्ष	1,94,380	100.0	76.7

Source: Annual Survey of Industries

बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) भी 2018–19 में 2011–12 की स्थिर कीमत पर मात्र 30,617 रूपये थी जो भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है जबकि भारत का औसत प्रतिव्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 92,565 रूपये है।

Source: Central Statistical Organization, GOI

इस सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि में बिहार से काफी संख्या में श्रमिक अपनी आजीविका की तलाश में अन्य बड़े शहरों एवं राज्यों की ओर पलायन करते हैं। पलायन के मामले में बिहार 13.43 प्रतिशत पलायन के साथ उत्तर प्रदेश (22.87 प्रतिशत) के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कुछ प्रमुख राज्यों के पलायन का प्रतिशत निम्न तालिका (8) में एवं रेखाचित्र में दर्शाया गया है–

तालिकाः 8

भारत में पलायन की दर (2001)

राज्य	पलायन की दर (%)
उत्तर प्रदेश	22.87
बिहार	13.43
राजस्थान	5.98
मध्य प्रदेश	5.07
प0 बंगाल	4.38
झारखंड	3.70
हरियाणा	3.54
छत्तीसगढ़	2.68
उड़ीसा	2.63

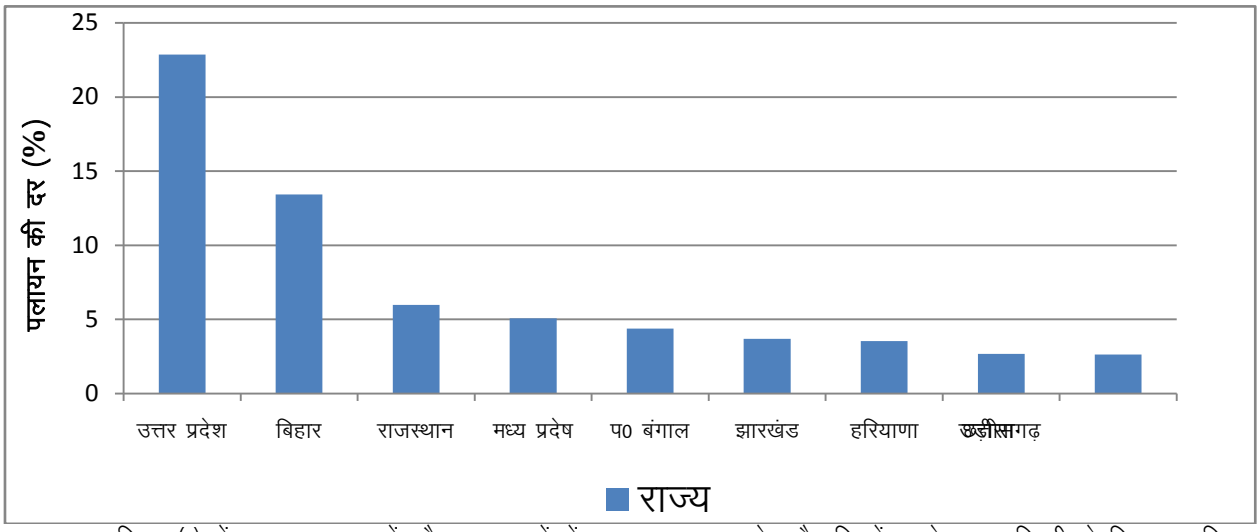

तालिका (9) में कुछ प्रमुख राज्यों और उन राज्यों में बिहार के श्रमिकों द्वारा पलायन करने के कारणों को दिखाया गया है। जैसा कि आँकड़ों से पता चलता है कि बिहार से कार्य/रोजगार के कारण सबसे ज्यादा 18 प्रतिशत पलायन दिल्ली के लिये होता है, जबकि रोजगार के लिये कुल पलायन करने वालों की संख्या 2.27 मिलियन है। दिल्ली के बाद दूसरे नम्बर पर झारखंड में 18 प्रतिशत पलायन होता है रोजगार के कारण। उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र 12 प्रतिशत एवं गुजरात 7 प्रतिशत है। व्यापार के कारण कुल 0.15 मिलियन लोग बिहार से पलायन करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा 31 प्रतिशत प0 बंगाल के लिए होता है। शिक्षा के कारण 0.12 मिलियन पलायन होता है। जिनमें सबसे ज्यादा दिल्ली के लिए 21 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 13 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत पलायन होता है। इसी तरह शादी के कारण सबसे ज्यादा पलायन (1.82 मिलियन) 31 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के लिए होता है। जबकि जन्म के बाद 0.17 मिलियन पलायन करनेवालों में 21 प्रतिशत प0 बंगाल के लिए होता है। सपरिवार पलायन 1.98 मिलियन में 20 प्रतिशत दिल्ली के लिए एवं अन्य कारणों से 0.95 मिलियन पलायन में सबसे ज्यादा 21 प्रतिशत प0 बंगाल के लिए होता है।

तालिकाः 9

Top five destinations of Bihar migrants for different reason, 2011

Work/Eemployment	Business	Education	Marriage	Moved after Birth	Moved with household	Others
Delhi (18)	West Bengal (31)	Delhi (21)	UP (31)	West Bengal (21)	Delhi (20)	West Bengal (21)
Jharkhand (13)	Assam (18)	UP(15)	Jharkhand (18)	Jharkhand (16)	Jharkhand (20)	Jharkhand (06)
West Bengal (12)	Odisha (10)	Jharkhand (13)	West Bengal (10)	Delhi (15)	West Bengal (20)	Delhi (15)
Maharshtra (12)	Jharkhand (10)	Mahrashtra (10)	Delhi (10)	Mahrashtra (13)	Mahrashtra (20)	Mahrashta (13)
Gujarat (7)	Gujurat (5)	Karnattaka (7)	Maharashra (5)	Punjab(1)	Gujarat (20)	Punjab (1)
Total 2.27 Million	Total 0.15 Million	Total 0.12Million	Total 1.82 Million	Total 0.17 Million	Total 1.98 Million	Total 0.95 Million

Source: Calculated from Census of India (2011)

ये प्रवासित व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग मनीऑर्डर के रूप में बिहार में रह रहे अपने परिवार को भी भेजते हैं जो परिवार की आय का एक साधन होता है। तालिका 10 में हम भारत के विभिन्न राज्यों के प्रवासित श्रमिकों द्वारा अपने घर पर भेजे गए मनीऑर्डर के प्रतिशत को देख सकते हैं। इसमें बिहार के 15 प्रतिशत परिवारों को देश के अन्दर विभिन्न राज्यों से मनीऑर्डर प्राप्ति होती है जबकि भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा भेजे गए कुल मनीऑर्डर का 12.4 प्रतिशत बिहार को प्राप्त होता है केवल आन्तरिक या देश के विभिन्न राज्यों से। जबकि विदेशी पलायन से 3 प्रतिशत परिवार को कुल 2.6 प्रतिशत मनीऑर्डर आय होती है भारत के कुल मनीऑर्डर आय का। (तालिकाः 10)

तालिकाः 10

Percentage Contribution to Migrant Households and Remittances Selected States

State	%to Total Households Report Remittances			%to Total Remittances Reported		
	Domestic	International	Total	Domestic	International	Total
Andhra Pradesh	3.3	8.5	4.0	3.0	7.7	4.6
Bihar	15.0	3.0	13.5	12.4	2.6	9.1

Kerala	3.2	38.6	7.7	5.2	39.9	16.9
Maharashtra	6.5	3.0	6.1	5.1	3.7	4.6
Orrisa	6.3	0.5	5.5	5.3	0.5	3.7
Punjab	0.8	7.6	1.7	2.2	12.7	5.7
Rajasthan	7.0	6.0	6.9	10.9	4.9	8.9
Tamil Nadu	5.5	15.3	6.7	6.2	12.4	8.3
Uttar Pradesh	24.6	8.3	22.6	19.6	5.4	14.8
West Bengal	8.6	1.7	1.7	7.9	1.2	5.8
All India	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Computed from unit data NSS 64th Round

कोविड– 19 के लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों से श्रमिकों की अपने मूल राज्य वापसी हो रही है। 22 जून 2020 में Livemint में अनुज ज्ञान वर्मा के एक लेख में कहा गया है कि जून 2020 में केन्द्र के द्वारा जारी एक आँकड़े के अनुसार इस समय सबसे ज्यादा रिवर्स पलायन बिहार में 23.6 श्रमिकों की हो चुकी है। दूसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश है जहाँ 17.6 लाख श्रमिकों का रिवर्स पलायन हुआ है। जबकि अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में अभी भी रिवर्स पलायन जारी है कोरोना के संकट के कारण। ऐसे में बिहार के सामने सबसे बड़ी समस्या इतने श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर तत्काल इनके भरण–पोषण की व्यवस्था करने की होगी।

साथ ही इनके परिवारों को इन श्रमिकों से जो मनीऑडर आय प्राप्त हो रही थी वह भी अब समाप्त हो गई है। इससे इन परिवारों की आय में कमी होगी। बेरोजगारी दर पहले से ही भारत के अन्य राज्यों से अधिक है इतने श्रमिकों की वापसी से और भी इसमें बढ़ोतरी होगी। परिवार में अधिक व्यक्ति के आने से पहले से उपलब्ध कृषि के लिए उपलब्ध भूमि पर और ज्यादा जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा।

इस समय कई श्रमिक कोरोना संक्रमण के साथ पलायन कर रहे हैं ऐसे में इनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी होगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में देश में 11,082 की आबादी पर मात्र एक डॉक्टर है। जबकि बिहार की स्थिति और भी खराब है। बिहार में 28,391 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर है। ऐसे में रिवर्स माइग्रेशन से कोरोना एवं अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना भी एक बड़ी समस्या है। यदि भारत सरकार समय से रिवर्स पलायन कर लौटे श्रमिकों के लिए रोजगार एवं जीविकोपार्जन की व्यवस्था नहीं कर पाई तो बिहार में चोरी–डकैती, भिक्षावृत्ति एवं अन्य सामाजिक अपराधों में वृद्धि होगी। इससे राज्य की कानून व्यवस्था भी खराब हो सकती है।

लेकिन इन चुनौतियों एवं समस्याओं के बावजूद भी यदि बिहार राज्य इन श्रमिकों के लिए सही नीति बनाकर इन श्रमिकों के रिवर्स पलायन को एक अवसर के रूप में ले और इनके स्किल को राज्य के विकास कार्यों में लगाये तो बिहार का काया पलट होना भी स्वभाविक है। Economic Times (मई, 2020) के एक न्यूज़ के अनुसार बिहार में विभिन्न योजनाओं में रोजगार के अवसरों के साथ ही कुशल श्रमिकों के लिए कुटीर उद्योग, कौशल विकास व स्वयं सहायता समूह जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। राज्य के बाहर से लौटे श्रमिकों का उनके स्किल के अनुसार डाटा तैयार किया जा रहा है। साथ ही निवेशकों से बात की जा रही है कि उन्हें किस तरह के श्रम की ज़रूरत है। अगर वास्तव में ये सम्भव हुआ तो श्रमिकों के लिए बिहार में फिर से एक नये अवसरर की शुरूआत होगी और भविष्य में श्रमिकों के पलायन में कमी आएगी।

निष्कर्ष

इस शोधपत्र में कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से बिहार में श्रमिकों के होने वाले रिवर्स पलायन का बिहार की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव एवं चुनौतियों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि श्रमिकों के रिवर्स पलायन से बिहार में बेराजगारी, गरीबी एवं भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा। लोगों की आय में कमी एवं बेरोजगारी बढ़ने से चोरी–डकैती, लूटपाट एवं भिक्षावृत्ति जैसे अपराधों में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखना एवं अतिरिक्त श्रमिकों को उनके स्किल के अनुसार रोजगार प्रदान करना राज्य के लिए एक चुनौती होगी। साथ ही रिवर्स पलायन से लौटे अतिरिक्त श्रमिकों के लिए कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इन समस्याओं एवं चुनौतियों के होते हुए भी सरकार इन श्रमिकों के स्किल का लाभ उठाकर सही योजना द्वारा उनको रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ राज्य का तेजी से विकास भी कर सकती है। इससे भविष्य में राज्य के पलायन में कमी आएगी।

सुझाव

1. सर्वप्रथम प्रवास से लौटे श्रमिकों का कोटीकरण किया जाय कि इन श्रमिकों की दक्षता किन–किन क्षेत्रों में है।
2. इसके अतिरिक्त जिस तरह के कार्य की उपलब्धता राज्य के अन्दर हो सकती है उसके अनुसार इन श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जाए।
3. कृषि आधारित ग्राम उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाय।
4. जिस क्षेत्र में बिहार की विशिष्टता है जैसे लिच्ची, लिट्टी–चोखा, मधुबनी पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन, भागलपुरी सिल्क इत्यादि के ज्यादा से ज्यादा प्रचार–प्रसार एवं इसके सही बाजारीकरण पर जोर दिया जाय।
5. उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाय।
6. किन्तु विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास तथा कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना होगा क्योंकि जब तक राज्य में शान्ति और सुरक्षा का सही माहौल नहीं होगा तो केवल सस्ते श्रम के बल पर निवेशक आकर्षित नहीं हो सकते हैं।
7. श्रमिकों के राष्ट्रीय राशन कार्ड एवं पहचान पत्र बनवाने पर जोर दिया जाय ताकि भविष्य में यदि ऐसी आपदा आती है तो इन श्रमिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सरकार के न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज के लाभों से वंचित नहीं होना पड़े।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *Bala Anju , " Migration in India ; Causes and consequences" International Journal of Advanced Educational Research, Volume - 2, Issue -4 , July 2017, page, 54-56*

2. *Centre for monitoring Indian Economy Report, ''लॉकडाउन से बेरोजगार हो गये 12 करोड़ से ज्यादा लोग'' (मई 6, 2020), नवजीवन डेस्क*
3. *Census report 1991, 2001, 2011*
4. *Economic survey of Bihar, 2019-20*
5. *Kumar Avinash 2 Kumar Manish, "Marginalised migrant and bihar as an area of origin." Home Journal, Volume-55, Issue no. 24, June 2020*
6. *Kumar Anshuman, as Migrant Laborers returns home, State governments prepare job opportunities." Economic Times, May 7, 2020*
7. *Mehta Balwant, " Covid 19 and the lockdown impact" Blogs (April 13,2020)*
8. *Raval .V, "Ownership Holdings of Land in Rural India: Putting the Record Straight." Economic and Political weekly, Vol-43, PP 43-77, (2008)*
9. *Sircar Jawahar, "A Long Look at exactly why and How India Failed Its migrant workers." The Wire (May, 29, 2020)*
10. *Jean Dreeze, "Bihar will take Worst Hit Due to Reverse Migration." Outlook Magzine (April 1, 2020)*
11. *Verma Anuj Gyan, "lockdown impact: over 41 lakhs migrant workers returns to Uttar Pradesh, Bihar (data released by centre June, 2020) Livemint, June 22, 2020.*
12. *एडम स्मिथ ''श्रम विभाजन'' , वैल्थ ऑफ नेशन्स (1776), प्रथम खण्ड, प्रथम अध्याय (Edwin Cannan द्वारा 1904 में प्रकाशित)*